मूल्य 1 रुपया

कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

कृषक समाचार की 32,000 प्रतियां सन् 1960 से हर महीने छापकर सदस्यों को भेजी जाती हैं

वर्ष 66 | अक्टूबर, 2021 | अंक 10 | कुल पृष्ठ 8

नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस का नेशनल सैंपल सर्वे की 2019 रिपोर्ट

नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस का नेशनल सैंपल सर्वे की सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसेज एंड लैंड एंड लाइवस्टॉक होल्डिंग्स ऑफ हाउसेज इन रूरल इंडिया (एसएएस) 2019 रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि खेती में किसानों की फसल से होने वाली आय की हिस्सेदारी कम हो रही है। अधिकांश वृद्धि मजदूरी और पशुपालन से आई है। फसलों से होने वाली आय की हिस्सेदारी 48 फीसदी से घटकर 38 फीसदी हो रह गई है

किसानों की फसलों से आय 48 फीसदी से गिर कर 38 फीसदी रह गई –एनएसओ

केंद्र की मोदी सरकार ने 2016 में घोषणा की थी कि साल 2022 तक किसानों की आय को दो गुना कर दिया जाएगा। यह बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की एक रैली में कही थी। लेकिन नेशनल सैंपल सर्वे की सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसेज एंड लैंड एंड लाइवस्टॉक होल्डिंग्स ऑफ हाउसेज इन रूरल इंडिया (एसएएस) रिपोर्ट, 2019 के जारी किए गये आंकड़े बताते हैं कि खेती में किसानों की दिलचस्पी कम हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि किसान की इनकम में अधिकांश वृद्धि मजदूरी और पशुपालन से आई है। खेती से होने वाली आय का हिस्सा वास्तव में 48 फीसदी से घटकर 38 फीसदी हो गया है ।

यह आंकडे नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस (एनएसओ) के अन्तर्गत आने वाले एसएएस द्वारा साल 2019 में लिए गये आंकड़ों के आधार पर जारी किया गए हैं। इस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार एक किसान कृषि सीजन जुलाई 2018–जून 2019 के दौरान हर महीने औसतन 10,218 रुपये कमाता था। जिसमें वह मजदूरी से 4023 रुपये कमा रहा था। जबकि फसलों से उनकी आय 3798 रुपये ही रही। इसकी तुलना अगर साल 2012 में लिए गये आंकड़ों से करें तो उस समय एक किसान परिवार हर महीने औसतन 6,021.45 रुपये कमा रहा था। उसमें से सिर्फ 621.69 रुपये मजदूरी से ही कमाए गए। जाहिर है कि 7 साल में किसानों की मजदूरी पर निर्भरता बढ़ी है। यानि किसान अब धीरे–धीरे मजदूर बन रहे हैं ।

किसान परिवार की मासिक कमाई (रुपये में)		
मजदूरी	–	4063
भूमि का पट्टा	–	134
फसल के माध्यम से शुद्ध आय	–	3798
पशुपालन	–	1582
गैर–कृषि व्यवसाय	–	641
कुल कमाई	–	10218

फसल की तुलना में पशुपालन और मजदूरी से ज्यादा आय

एक किसान परिवार कृषि के अलावा अन्य स्रोतों से कमा सकता है, 2018–19 में मजदूरी, खेती, पशुपालन और गैर–कृषि व्यवसाय की हिस्सेदारी 40 फीसदी, 38 फीसदी, 16 फीसदी और 6 फीसदी थी। 2012–13 में ये शेयर 32 फीसदी, 48 फीसदी,12 फीसदी और 8 फीसदी जैसे मजदूरी या गैर–कृषि व्यवसाय से आई थे। इससे पता चलता है कि एक व्यवसाय के रूप में फसल उत्पादन से आय में गिरावट आ रही है। इससे यह पता चलता है कि यह उनकी आय का सबसे बड़ा स्रोत भी नहीं है और किसान परिवार केवल खेती से आय अर्जित नहीं करते हैं।

साल 2012 के दौरान किसानों की कुल मासिक आय 6021.45 रुपये थी। इस मासिक आय में जुलाई–दिसंबर सीजन के दौरान 50 प्रतिशत फसलों से अर्जित करता था। लेकिन 2019 में फसलों से होने वाला आय घटकर 38 फीसदी रह गया है। क्योकि कुल मासिक आय 10218 रुपये में फसल से केवल 3798 रुपये कमा रहे हैं।

अगर आंकडों पर गौर करें तो प्रति किसान के परिवार की फसल उत्पादन से आय 2018–19 में 3,798 रुपये थी, जो 2012–13 की तुलना में 23 फीसदी अधिक है। हालांकि, वास्तविक रूप में इसमें 8.9 फीसदी की गिरावट आई है।

निश्चित रूप से, इस तरह की गिरावट तब भी हो सकती है जब किसान परिवार खेती के साथ पशुपालन करते पशुपालन में रुचि लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन वे फसलों के उत्पादन से कमाई नहीं करते हैं। इसलिए वास्तव में प्रत्येक किसान परिवार जो केवल फसल उत्पादन में लगे है इस तरह आय में हो रहे परिवर्तन जरूर देखना चाहिए। अकेले फसलों की खेती और इससे संबंधित गतिविधियों से, लगे परिवारों की वास्तव में शुद्ध नाममात्र आय जो 2012–13 में 3,350 रूपये थी और 2018–19 में 4,001 रुपये थी, इस तरह 19 फीसदी अधिक है। वास्तविक रूप में इस तरह की आय में 11.7 फीसदी की गिरावट आई है।

आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल कृषि का प्रदर्शन खराब नहीं रहा है, हालांकि वे इस तथ्य को नाकरा नही जा सकता की फसल और उससे संबद्ध गतिविधियों के आय में वास्तविक रूप से गिरावट आई है जबकि पिछले सात सालो किसानो को मानसून ने धोखा नहीं किया है

किसान पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है

सर्वे के अनुसार, 2018–19 में एक किसान परिवार का औसत कर्ज 58 फीसदी

बढ़कर 74,100 रुपया हो गया, जो 2012–13 के दौरान 47,000 रूपया था। वास्तविक रूप में यह 16.5 फीसदी की वृद्धि है। लेकिन बकाया ऋण वाले कृषि परिवारों की हिस्सेदारी 51.9फीसदी से घटकर 50.2 फीसदी हो गई।

जुलाई 2018–जून 2019 की अवधि के किसान परिवारों की स्थिति लिए डेटा सबसे व्यापक है । इस सर्वेक्षण का पिछला दौर 2013 में आयोजित किया गया था और जुलाई 2012–जून 2013 की अवधि के लिए डेटा एकत्र किया गया था। मोदी सरकार के तहत किसानों की स्थिति का यह पहला कंप्रेसिव अकाउंट है।

एसएएस द्वारा दो दौर में लिए गये डाटा के अनुसार साल 2012–13 और 2018–19 के बीच ग्रास वल्यू एडेड का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 3.6 फीसदी था । एसएएस किसान परिवारों की औसत आय का डेटा देता है मगर किसानों की स्थिति के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता है। 2018 –19 में जो आंकडे लिए गये है जिसमें किसानों की आय 10,218 रुपये प्रति माह इनकम थी उसमे घरेलू आय के अलावा किसान की जमीन को लीज पर दी गई आय को शामिल किया गया था जबकि साल 2012–13 में शामिल नहीं किया गया था। इस तरह बिना लीज जमीन के इनकम को निकालने पर 2018–19 में औसत घरेलू आय 10,084 रुपये है।

सर्वे में उन किसान परिवार को शामिल किया जाता रहा है जो खेत या बागवानी फसलों, पशुधन या अन्य जूड़े हुए कृषि गतिविधियों के उत्पादों का उत्पादन करता है, भले ही उसके पास कोई भूमि न हो या संचालित न हो। नगण्य उत्पादन वाले परिवारों को बाहर करने के लिए, पिछले 365 दिनों में कृषि में स्व–नियोजित सदस्य वाले परिवारों पर विचार किया जाता है साथ ही केवल 4,000 रुपये से अधिक की उपज का मूल्य प्राप्त करने वाले किसान परिवार को शामिल किया जाता ।

जे पी सिंह (रूरलवॉयस)

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

"भविष्य के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य" कार्यशाला

27–30 अगस्त 2021,
बैंगलोर (कर्णाटक)

भारत कृषक समाज और सोक्रेटस फाउंडेशन फॉर कलेक्टिव विजडम ने भविष्य के लिए एमएसपी की कल्पना करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें 24 प्रभावशाली हितधारकों के एक चुनिंदा समूह ने भाग लिया। प्रतिभागियों को सभी दृष्टिकोणों और हितधारकों (शिक्षा, केंद्र और राज्य सरकारों, नागरिक समाज, किसान संघों, कृषि व्यवसाय, मीडिया और राजनीतिक प्रतिनिधियों) का प्रतिनिधित्व करने के लिए सावधानीपूर्वक चुना गया है।

"भविष्य के लिए एमएसपी"

प्रतिभागियों की सामूहिक तस्वीर

प्रस्तावना – एमएसपी एक बुरी समस्या है

दुनिया भर में, सरकारें खाद्य सुरक्षा की चिंता के कारण किसानों का समर्थन करती हैं। सहायता विभिन्न तंत्रों के माध्यम से प्रदान की जाती है। भारत में, *24* फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य *(MSP)* और एक सार्वजनिक खरीद प्रणाली है जो इसे मूल्य समर्थन तंत्र के रूप में समर्थन करती है। हालांकि इस प्रणाली ने कुछ तरीकों से काम किया है, एक मान्यता है कि इसकी संरचना, कार्यान्वयन और संचालन किसानों, उपभोक्ताओं और पर्यावरण की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित होना चाहिए।

एमएसपी को फिर से डिजाइन करने के बारे में सोचना केवल एक तकनीकी चुनौती नहीं है, बल्कि इसमें भोजन की राजनीति, खाद्य मुद्रास्फीति, केंद्र–राज्य संबंधों की बदलती गतिशीलता, व्यवसायों की उभरती भूमिका और बदलती नीतियों के संक्रमणकालीन दर्द पर विचार करने की आवश्यकता है। इन कारणों से, एमएसपी की संरचना एक बड़ी समस्या है जिसके लिए अलग–अलग दृष्टिकोण रखने वाले लोगों को बहस से परे जाने और आगे के तरीकों को सह–निर्माण करने के लिए एक–दूसरे को समझने के गहन, सम्मानजनक अभ्यास में संलग्न होने की आवश्यकता होती है।

चार दिनों के कार्यशाला को इस हिसाब से तैयार किया गया था ताकि प्रतिभागियों को स्वाभाविक रूप से अपने विचारों को खोलने, दूसरों के साथ संरेखित करने, सार्वजनिक प्रतिबद्धताओं को बनाने और फिर प्रतिबद्धता की उस स्थिति से आगे बढ़ने के लिए निर्देशित किया जा सके।

प्रतिभागियों की सूची:

- श्री अभिषेक जैन
  फेलो और डायरेक्टर – पॉवरिंग लाइवलीहुड, सीईईडब्ल्यू
- श्री अनिल घनवत
  अध्यक्ष, शेतकारी संगठन
- श्री आलोक सिन्हा
  पूर्व अध्यक्ष, एफसीआई
- श्री अमित अग्रवाल
  सीईओ, एग्रीबाजार
- डॉ अविनाश किशोर
  रिसर्च फेलो, आईएफपीआरआई
- श्री बिराज पटनायक
  कार्यकारी निदेशक, नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया
- प्रो. सीएससी शेखर
  आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय
- श्री दीपक गुप्ता
  पूर्व कमोडिटीज हेड फॉर एशिया, कारगिल
- श्री दिनेश कुलकर्णी
  अखिल भारतीय आयोजन सचिव, भारतीय किसान संघ
- डॉ. दीपा सिन्हा
  सहायक प्रोफेसर, अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली
- श्री हरवीर सिंह पंवार
  प्रधान संपादक, रूरल वॉयस
- डॉ हिमांशु
  सहायक प्रोफेसर अर्थशास्त्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

- श्री जयंत चटर्जी
  सीओओ, स्टारएग्री लिमिटेड
- सुश्री कविता कुरुगंती
  सह–संयोजक, एलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर
- श्री कन्नन गोपीनाथन
  पूर्व आईएएस, सामाजिक कार्यकर्ता
- श्री पुनीत सिंह थिंड
  नॉदर्न फार्मर्स मेगा एफपीओ
- श्री रवनीत बराड़
  प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन (कादियान)
- सुश्री रेजाथा वी
  उप. कृषि निदेशक, केरल
- श्री सयंतन बेरा
  राष्ट्रीय लेखक, मिंट, हिंदुस्तान टाइम्स, दिल्ली
- डॉ शंभू प्रसाद
  प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, आनंद
- श्री सुरेंद्र प्रसाद सिंह
  पत्रकार, दैनिक जागरण
- श्री सुनील कुमार सिंह
  एडिशनल एमडी, नेफेड
- श्री टी नंदा कुमार
  फॉर्मर सेक्रेट्री मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, सेवानिवृत्त आईएएस
- श्री अनुपम कौशिक
  अध्यक्ष, नेशनल कोलेटरल मैनेजमेंट

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

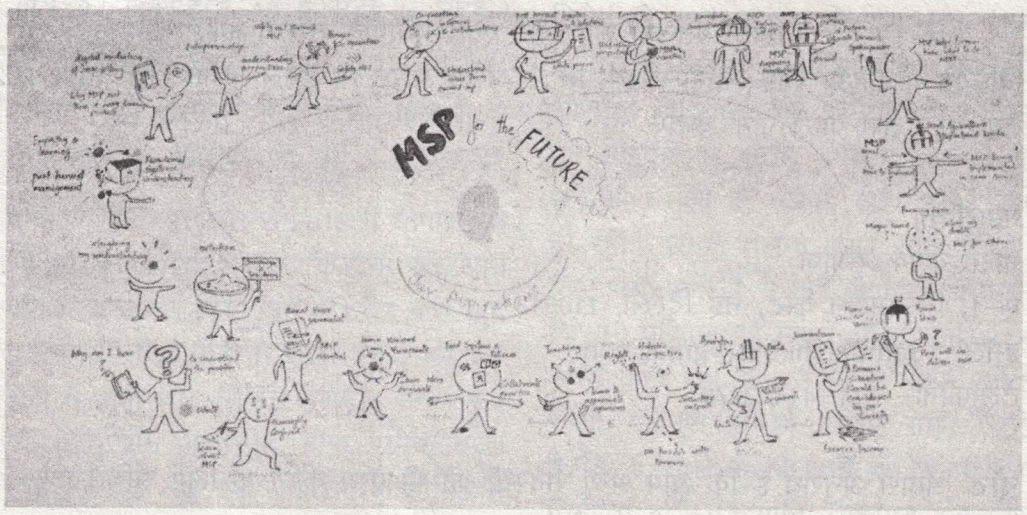

RNI No. 831/1957
पोस्टल रजि० DL (S)-01/3092/2021-23
पहले भुगतान किये बिना पोस्ट करने का लाइसेंस नं.
U(C)-92/2021-23

प्रकाशन की तिथि : 1 अक्टूबर, 2021
एल.पी.सी., दिल्ली आर.एम.एस, दिल्ली–6,
तारीख 4 एवं 5, अक्टूबर 2021

सार्वजनिक सूचना

भारत कृषक समाज के सदस्यों से अनुरोध है कि वे भारत कृषक समाज के महासचिव के कार्यालय के साथ अपने संपर्क विवरण को अद्यतन करें।

संपर्क विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है:

नामः _____

सदस्यता संख्याः _____

वर्तमान पताः _____

_____

टेलीफोन नंबरः _____

मोबाइल नंबरः _____

ईमेलः _____

(कृपया पते का सबूत की एक छायाप्रति संलग्न करें)

विधिवत भरा हुआ फॉर्म निम्नलिखित पते पर स्पीड पोस्ट या ईमेल दिनांक 30 नवंबर 2021 तक या उससे पहले जमा कराएं:

महासचिव
भारत कृषक समाज
ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली, 110013
ईमेलः– Samdarshi.bks@gmail.com
टेलीफोनः– 011–41402278

नोटः आपसे अनुरोध है कि आप अन्य सदस्यों को भी ऐसा करने के लिए सूचित करे।

भारत कृषक समाज ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली– 110013, फोनः 011–41402278, 9667673186, ई–मेलः ho@bks.org.in, **वैबसाईटः** www.bks.org.in **के लिए श्री उरविन्द्र सिंह भाटिया द्वारा सम्पादित, मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरेस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस –2, नई दिल्ली –110020 द्वारा मुद्रित।**